डॉ. सुब्रमण्यन स्वामी

बनाम.

अरुण शौरी

(अवमानना याचिका (सीआरएल) संख्या 11/1990)

23 जुलाई, 2014

[आर. एम. लोढा, सीजेआई, अनिल आर.देव, सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय, दीपक मिश्रा और शिवा कीर्ति सिंह, न्यायाधिपतिगण]

न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971:

धाराये 10ए और 15 सपठित भारत के संविधान का अनुच्छेद- अवमानना कार्यवाही - की पोषणीयता - सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत गठित आयोग की रिपोर्ट की आलोचना करने के कार्य के लिए - अभिनिर्धारित : 1952 अधिनियम के तहत नियुक्त एक आयोग में है वैधानिक आयोग की प्रकृति - यह वास्तव में एक तथ्य-खोज निकाय है - इसे पक्षकारो के अधिकारों पर निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है और इसका कोई न्यायिक कार्य नहीं है - इसके निष्कर्षों का कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है- इसलिए, ऐसा आयोग 1971 अधिनियम का उद्देश्य के लिये न्यायालय नहीं है- केवल इसलिए कि ऐसे आयोग का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश द्वारा किया जाता है, यह सुप्रीम कोर्ट की विस्तारित शाखा नहीं बन जाता है- वर्तमान अवमानना कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती थी - धारा 10ए उच्च न्यायालय के संदर्भ में आयोग को रचनात्मक अवमानना की शक्ति प्रदान करती है - धारा 15 के तहत स्वत: संज्ञान के तहत शुरू की गई अवमानना कार्यवाही और खारिज की गई- भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 129.

धारा - 13 (2006 के अधिनियम 6 द्वारा प्रतिस्थापित) - अवमानना कार्यवाही में बचाव के रूप में सत्य - अभिनिर्धारित किया गया : अदालतों को बचाव के रूप में सत्य की अनुमति देनी चाहिए, यदि वह संतुष्ट है कि यह सार्वजनिक हित में है और उक्त बचाव को लागू करने का अनुरोध प्रामाणिक है।

शब्द और वाक्यांश - 'न्यायालय' - का अर्थ, न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 के संदर्भ में - प्रत्येक न्यायालय में कम से कम तीन घटक भाग होने चाहिए- 'अभिनेता', 'रेउस' और 'ज्यूडेक्स' यानी शिकायतकर्ता, प्रतिवादी और न्यायिक शक्ति- जांच आयोग अधिनियम के तहत गठित एक आयोग न्यायालय के पूर्व-प्रतिष्ठित परीक्षणों को पूरा नहीं करता है।

प्रतिवादी ने एक संपादकीय प्रकाशित किया था, जिसमें उन्होंने जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत गठित जांच आयोग के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह (सर्वोच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश) द्वारा दी गई रिपोर्ट की आलोचना की थी।

संपादकीय के मद्देनजर, इस न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत स्वत: संज्ञान लेते हुए अवमानना याचिका शुरू की। अपीलकर्ता ने भी न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 15 के अंतर्गत अवमानना याचिका दायर की प्रतिवादी के विरुद्ध दायर की ।

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने अटॉर्नी जनरल की राय प्राप्त की, जिन्होंने कहा कि संपादकीय ने प्रथम दृष्टया अनुमेय आलोचना की सीमा का उल्लंघन किया है; और यह कि अवमानना का कानून, जैसा कि देश में मौजूद था, बचाव के रूप में सच्चाई प्रदान नहीं करता था और इसलिए स्पष्टीकरण के लिए नोटिस जारी किया जा सकता था।

दोनों अवमानना मामलों को दो प्रमुख प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए संविधान पीठ को भेजा गया था। (i) क्या अवमानना कार्यवाही में सत्य को बचाव के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है? और (ii) जब सर्वोच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश को 1952 अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो क्या उसके पास सर्वोच्च न्यायालय की सभी शक्तियां और अधिकार क्षेत्र होते हैं?

कोर्ट ने अवमानना याचिकाएं खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित किया : 1. अवमानना कार्यवाही में बचाव के रूप में सत्य के संबंध में कानूनी स्थिति वैधानिक रूप से अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 13 (2006 के अधिनियम 6 द्वारा प्रतिस्थापित) द्वारा तय की गई है। खंड 13(बी), स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि अवमानना कार्यवाही में सत्य वैध बचाव हो सकता है। न्यायालय सत्य को बचाव के रूप में अनुमति दे सकता है, यदि दो बातें संतुष्ट हों, अर्थात, (i) यह सार्वजनिक हित में है और (ii) उक्त बचाव को लागू करने का अनुरोध प्रामाणिक है। [पैरा 13 से 15][594-बी; 595-बी; एफ]

इनडायरेक्ट टैक्स प्रैक्टीशनर्स एसोसियेशन बनाम आर.के. जैन (2010) 8 एससीसी 281 - पर भरोसा किया।

एम्बर्ड बनाम अटॉर्नी-जनरल ऑफ त्रिनिदाद और टोबैगो (1936) एसी 322; नेशनवाइड न्यूज प्राइवेट लिमिटेड बनाम विल्स (1992) 177 सीएलआर 1 - संदर्भित किया गया।

2.1. जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत नियुक्त आयोग के कार्य न्यायिक कार्यों या न्यायिक शक्ति का निर्वहन करने वाली संस्था की तरह नहीं हैं।

1952 अधिनियम के तहत नियुक्त आयोग एक न्यायालय नहीं है और आयोग द्वारा तथ्यों की जांच या निर्धारण करना न्यायिक चरित्र का नहीं है। [पैरा 23]

2.2. हालाँकि न्यायालय की अवमानना अधिनियम 'न्यायालय' शब्द को परिभाषित नहीं करता है, लेकिन उस अधिनियम के तहत 'न्यायालय' का अर्थ वह प्राधिकारी है जिसके पास निर्णय देने की कानूनी शक्ति है, जिसकी पुष्टि यदि किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा की जाती है, तो वह निश्चित होगा। न्यायालय एक संस्था है जिसके पास निश्चित निर्णय देकर कानूनी अधिकारों को विनियमित करने और कानूनी मंजूरी द्वारा अपने आदेशों को लागू करने की शक्ति है और यदि साक्ष्य लेने और शपथ लेने जैसे मामलों में इसकी प्रक्रिया न्यायिक है, तो यह एक अदालत है। अधिनियम 1952 के तहत गठित आयोग न्यायालय के इन प्रमुख परीक्षणों को पूरा नहीं करता है। [पैरा 25][602-बी-डी]

2.3. प्रत्येक न्यायालय में, 'अभिनेता', 'रेउस' और 'ज्यूडेक्स' कम से कम तीन घटक भाग होने चाहिए: 'अभिनेता', जो चोट लगने की शिकायत करता है; 'रेउस' या प्रतिवादी, जिसे संतुष्टि देने के लिए बुलाया जाता है; और 'ज्यूडेक्स' या न्यायिक शक्ति, जो तथ्य की सच्चाई की जांच करती है और तथ्य पर उत्पन्न होने वाले कानून का निर्धारण करती है और यदि कोई चोट लगती है, तो पता लगाती है, और अपने अधिकारियों द्वारा उपाय लागू करती है। [पैरा 26] [602-ई-एफ]

2.4. 1952 अधिनियम के तहत नियुक्त एक आयोग एक वैधानिक आयोग की प्रकृति में है और केवल इसलिए कि जांच आयोग का नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश द्वारा किया जाता है, यह इस न्यायालय की विस्तारित शाखा नहीं बन जाता है। 1952 अधिनियम के तहत गठित आयोग एक तथ्य-खोज निकाय है जो उपयुक्त सरकार को यह निर्णय लेने में सक्षम बनाता है कि क्या कार्रवाई की जानी है।

ऐसे आयोग को पक्षकारो के अधिकारों पर निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है और इसका कोई न्यायिक कार्य नहीं है। सरकार इसकी सिफ़ारिशों को स्वीकार करने या इसके निष्कर्षों पर कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है। केवल यह तथ्य कि आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया कानूनी चरित्र की है और उसे शपथ दिलाने की शक्ति है, उसे न्यायालय का दर्जा नहीं मिल जाएगा। ऐसा होने पर, 1952 अधिनियम के तहत नियुक्त आयोग न्यायालय की अवमानना अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक न्यायालय नहीं है, भले ही इसका नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। [पैरा 34][608-बी-ई]

भारत बैंक लिमिटेड, दिल्ली बनाम भारत बैंक लिमिटेड के कर्मचारी, दिल्ली 1950 एससीआर 459 एआईआर 1950 एससी 188 - अनुसरण किया गया।

ब्रजनंदन सिन्हा बनाम ज्योति नारायण (1955) 2 एससीआर 955; मकबूल हुसैन बनाम बॉम्बे राज्य 1953 एससीआर 730 = एआईआर 1953 एससी 325; एस.ए. वेंकटरमन बनाम भारत संघ 1954 एससीआर 1150 एआईआर 1954 एससी 375; श्री राम कृष्ण डालमिया बनाम श्री न्यायमूर्ति एस.आर. तेंडुलकर और अन्य 1959 एससीआर 279; डॉ. बलिराम वामन हिरय बनाम न्यायमूर्ति बी. लेंटिन और अन्य 1988 (2) पूरक एससीआर 942 (1988) 4 एससीसी 419- भरोसा व्यक्त किया गया।

हडार्ट पार्कर एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाम मूरहेड 8 सीएलआर 330; ऑस्ट्रेलिया की शेल कंपनी, लिमिटेड बनाम संघीय कराधान आयुक्त (1931) एसी 275; रोला कंपनी (ऑस्ट्रेलिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम कॉमनवेल्थ 69 सीएलआर 185; पुन: श्री हेल्स, "द मेल" के संपादक और अन्य एआईआर 1955 मद्रास 1; पी. राजंगम, पुलिस उपनिरीक्षक एवं अन्य बनाम मद्रास राज्य और अन्य एआईआर 1959 मद्रास

294; एम.वी.राजवाड़े, आई.ए.एस., जिला मजिस्ट्रेट बनाम डॉ. एस.एम. हसन और अन्य. एआईआर 1954 नागपुर 71 - संदर्भित किया गया।

2.5. इसके अलावा, 1952 अधिनियम की धारा 10ए में उच्च न्यायालय के बारे में कोई संदेह नहीं है। आयोग या उसके किसी सदस्य को बदनाम करने वाले कृत्यों के संबंध में शिकायत का संज्ञान लेने की शक्ति प्रदान की गई। धारा 10ए इस न्यायालय में अपील के अधिकार के साथ उच्च न्यायालय का संदर्भ देकर आयोग को रचनात्मक अवमानना की शक्ति प्रदान करती है। [पैरा 34][608-ई-एफ]

प्रकरण कानून संदर्भ:

(1936) एसी 322	संदर्भित किया गया	पैरा 11
(1992) 177 सीएलआर 1	संदर्भित किया गया	पैरा 11
(2010) 8 एस. सी. सी. 281	संदर्भित किया गया	पैरा 16
1950 एससीआर 459	संदर्भित किया गया	पैरा 27
8 सीएलआर 330	संदर्भित किया गया	पैरा 27
(1931) एसी 275	संदर्भित किया गया	पैरा 27
69 सीएलआर 185	संदर्भित किया गया	पैरा 27
(1955) 2 एससीआर 955	संदर्भित किया गया	पैरा 28
1953 एससीआर 730	संदर्भित किया गया	पैरा 28
1954 एससीआर 1150	संदर्भित किया गया	पैरा 28
एआईआर 1955 मद्रास 1	संदर्भित किया गया	पैरा 30
ए. आई. आर. 1959 मद्रास 294	संदर्भित किया गया	पैरा 31

1959 एससीआर 279 भरोसा व्यक्त किया पैरा 32

1988 (2) पूरक। एस. सी. आर. 942 भरोसा व्यक्त किया पैरा 33

एआईआर 1954 नागपुर 71 संदर्भित किया गया पैरा 33.1

आपराधिक मूल क्षेत्राधिकार : अवमानना याचिका (आपराधिक) सं. 11/1990

में

अवमानना याचिका (आपराधिक) सं. 12/1990

मोहन परासरन, एस. जी. , अशोक एच. देसाई, अरविंद दातार, श्री एड. , भरत संगल, सुश्री माधवी दीवान, सुश्री बीना गुप्ता, अभय ए. जेना और हर्ष देसाई, अधिवक्तागण, पक्षकारो के लिये उपस्थित होते हुये।

न्यायालय का निर्णय आर. एम. लोढ़ा, मुख्य न्यायाधिपति द्वारा सुनाया गया। 1. इंडियन एक्सप्रेस के 13 अगस्त 1990 के अंक में "अगर शर्म बची होती" शीर्षक से एक संपादकीय प्रकाशित हुआ था। संपादकीय इस प्रकार है:

"अगर शर्म बची होती"

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री वाई. वी. चंद्रचूड़ ने कुलदीप सिंह आयोग की रिपोर्ट पर जो कानूनी राय दी है, वह एक आश्चर्यजनक अभियोग है। सम्मानजनक होने की हद तक संक्षिप्त, तथ्यों और कानून का ईमानदारी से पालन करना, आयोग के लिए किसी भी मकसद का थोड़ा सा भी आरोप पूरी तरह से त्यागना, राय शुद्धता का एक मॉडल है। रिपोर्ट में ऐसा कोई भी "प्रमाण" नहीं बचा है कि इस बात पर सहमति हुई थी कि इसे आधार के रूप में नहीं माना जाएगा; उस एक गवाह के साक्ष्य को, जो निर्णयों का केंद्र था, पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया; "संभावित संभावना" पर लगाए गए अभियोग, दस्तावेजों में अर्थ पढ़ने के लिए आविष्कार किए गए सिद्धांत

और प्रकट, सीधी व्याख्या को नजरअंदाज कर दिया गया; स्वयं आयोग और साथ ही ऊर्जावान अभियोजक ने एक दिन घोषणा की कि दोनों के पास कोई सबूत नहीं है जो हेगड़े पर संदेह पैदा करता हो और अगले ही दिन निष्कर्ष की घोषणा कर दी; आम गवाहों को इस बहाने से जिरह के लिए मना करना कि आयोग के पास उन्हें बुलाने की शक्ति नहीं है-इसके विपरीत स्पष्ट निर्णयों के सामने; फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की एक धारा लागू करना जो मृत्यु पूर्व बयान देने वाले व्यक्ति पर लागू होती है; इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि जिस व्यक्ति को लाभ मिलने की बात कही जा रही है, उसने अपने द्वारा जमा किए गए 55 लाख रुपये खो दिए हैं; संकेत देना - और संकेत पर एक संपूर्ण अभियोग बनाना - कि बिल्डर ने एक झूठी साजिश रची थी, जबकि वास्तविक रिकॉर्ड से पता चलता है कि वह सब कुछ खुले तौर पर और सभी औपचारिकताओं के साथ कर रहा था जिसकी कानून को आवश्यकता है; इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि जमीन बिल्डर को अधिग्रहण की लागत से तीन गुना पर दी जानी थी और इसके ऊपर अधिग्रहण की लागत से 4 से 6 गुना तक विकास शुल्क लगाया जाना था; इस तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए कि भूमि कभी हस्तांतरित नहीं की गई थी और यह केवल तत्कालीन मुख्यमंत्री के आग्रह के कारण हस्तांतरित नहीं की गई थी कि नियम बनाए जाएं जिसके तहत ऐसे सभी मामलों से निपटा जाएगा। यह सप्रेसो वेरी सजेस्टो फाल्सी की सबसे लंबी संभावित सूची है।

यदि सम्मान या शर्म की कोई भावना होती तो कोई न्यायाधीश ऐसा कभी नहीं करता। यदि सम्मान या शर्म की कोई भी भावना बची होती, तो ऐसा करने और ऐसा करते पाए जाने पर न्यायाधीश ने अपनी सीट खाली कर दी होती। लेकिन ये भारत है. 1990 में, कमिश्नर कुलदीप सिंह ने ऐसी विकृतियाँ कीं, जो अनगिनत नागरिकों के भाग्य और प्रतिष्ठा पर फैसला सुनाते रहेंगे। वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय से भी कम स्तर से ऐसा करना जारी रखेंगे।

ऐसी ही हमारी हालत है। और हम इतने असहाय हैं कि ऐसे "न्यायाधीश" के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। एक बात बचा लो। ऐसे व्यक्तियों द्वारा नागरिकों को पहुंचाई जाने वाली चोटों को कम करने का एकमात्र तरीका यह है कि हम सभी उनके द्वारा सौंपे गए अभियोगों या प्रमाणपत्रों की पूरी तरह से जांच करें। केवल वही अभ्यास इन अभियोगों और विकृतियों के प्रमाण-पत्रों को प्रदर्शित करेगा जो वे हैं और केवल इसी तरीके से उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। "बड़ी-बड़ी रिपोर्टें पढ़ने, सबूत छांटने का समय किसके पास है?" लेकिन अगर मुद्दा हमारे लिए इस पर राय बनाने के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण है, तो यह हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसी रिपोर्टों की जांच करने के लिए समय निकालें, साथ ही उन आयुक्तों के आचरण की भी जांच करें जो उन्हें अंजाम देते हैं।"

2. ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रामकृष्ण हेगड़े द्वारा चूक और कमीशन के कथित कृत्यों की जांच के लिए जांच आयोग अधिनियम, 1952 (इसके बाद '1952 अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत जांच आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता वाले एक सदस्यीय आयोग ने 22.06.1990 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

3. ये दो अवमानना मामले, एक डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा और दूसरा स्वत: संज्ञान से इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित संपादकीय से उत्पन्न हुए हैं, जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है। डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा 23.08.1990 को इंडियन एक्सप्रेस के तत्कालीन संपादक श्री अरुण शौरी के खिलाफ अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 (इसके बाद "1971 अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 15 के तहत दायर अवमानना याचिका में, यह तर्क दिया गया है कि संपादकीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश और न्यायपालिका के संबंध में एक निंदनीय

बयान है। यह इस न्यायालय के अधिकार को कम करता है और साथ ही इसमें जनता के विश्वास को हिलाता है और इस न्यायालय की आपराधिक अवमानना के समान है। यह प्रस्तुत किया गया है कि जब तक यह न्यायालय तुरंत कार्रवाई नहीं करता है और यदि आवश्यक हो, तो मामले में स्वत: संज्ञान नहीं लेता है, मौजूदा न्यायाधीश असहाय होंगे और अपना बचाव करने में असमर्थ होंगे, और इस प्रक्रिया में, न्यायाधीशों और अदालतों में जनता का विश्वास खत्म हो जाएगा।

4. यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले में भारत के अटॉर्नी जनरल की राय ली थी। तत्कालीन अटॉर्नी जनरल श्री सोली सोराबजी ने दिनांक 27.08.1990 को अपनी राय में कहा कि संपादकीय ने, प्रथम दृष्टया, अनुमत आलोचना की सीमा को पार कर लिया है और अवमानना का कानून, जैसा कि देश में मौजूद था, बचाव के रूप में सच्चाई प्रदान नहीं करता था और इसलिए, उन्होंने राय दी कि स्पष्टीकरण मांगा गया है और इसके लिए नोटिस उस उददेश्य के लिये जारी किया जा सकता है। उनके विचार में, यह प्रश्न कि क्या 1952 अधिनियम के तहत नियुक्त आयोग या आयुक्त की अवमानना उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के समान है, जिसका आयुक्त सदस्य है, समस्या की पुनरावृत्ति को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आधिकारिक तौर पर इसका निपटारा किया जाना चाहिए।

5. 03.09.1990 को, स्वत: संज्ञान अवमानना मामला और डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर अवमानना याचिका भी माननीय मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष विचार के लिए आई। 03.09.1990 की कार्यवाही इस प्रकार है:

"इन रे: अरुण शौरी और अन्य।

हमने 13 अगस्त, 1990 के "इंडियन एक्सप्रेस" का संपादकीय देखा है। हमने इस मामले में भारत के अटॉर्नी जनरल की राय प्राप्त की है। हम मानते हैं कि संपादकीय के पैराग्राफ 2 और 3 अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2(सी) में 'आपराधिक अवमानना' की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। इसलिए, हम निर्देश देते हैं कि कथित अवमाननाकर्ताओं को यह बताने के लिए जारी नोटिस 8 अक्टूबर, 1990 को वापस किया जाए कि उनके द्वारा प्रकाशित अपमानजनक संपादकीय के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत इस न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। अवमाननाकर्ता 8 अक्टूबर 1990 को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होंगे। मामले में अटॉर्नी जनरल द्वारा दी गई राय की एक प्रति अवमाननाकर्ताओं को जारी किए जाने वाले नोटिस के साथ होनी चाहिए। वे 8 अक्टूबर 1990 को या उससे पहले अपने बचाव के समर्थन में अपना हलफनामा दायर कर सकते हैं।

भारत के अटॉर्नी जनरल को उपस्थित होने और मामले की सुनवाई में अदालत की सहायता करने के लिए नोटिस जारी करें।

<u>अवमानना याचिका संख्या. 1990 का:</u>

भारत के विद्वान अटॉर्नी जनरल ने भी हमारा ध्यान 'करंट' (25-31 अगस्त, 1990) के एक अंक की ओर आकर्षित किया है जिसमें एम.वी. कामथ का एक लेख है। हम उस मामले पर बाद में अलग से विचार करेंगे.

<u>डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम श्री अरुण शौरी:</u>

8 अक्टूबर, 1990 को नोटिस जारी करें जिसमें बताया जाए कि अवमानना कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए।

6. प्रतिवादी अरुण शौरी ने 13.10.1990 को अपना उत्तर हलफनामा प्रस्तुत किया। हम थोड़ी देर बाद उचित स्थान पर उनके बचाव और आपत्तियों का उल्लेख करेंगे। हालाँकि, इस स्तर पर यह नोट करना पर्याप्त होगा कि जवाबी हलफनामे में, प्रतिवादी ने प्रार्थना की कि, तथ्यों की संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए, वह उन तथ्यों को हलफनामे में शामिल करने से बचना चाहेगा, लेकिन उन्हें शामिल करना पसंद करेगा। न्यायालय के अवलोकन के लिए सीलबंद लिफाफे में एक हस्ताक्षरित बयान का रूप जिसे प्रति शपथ पत्र का अभिन्न अंग माना जा सकता है। हालाँकि, न्यायालय ने 04.03.1991 को उनकी प्रार्थना को खारिज कर दिया और पाया कि प्रतिवादी द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया स्वीकार्य प्रक्रिया नहीं थी और दलीलों के मान्यता प्राप्त स्वरूप के साथ असंगत थी। प्रतिवादी को न्यायालय से सीलबंद लिफाफे को वापस लेने की छूट दी गई। उन्हें अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने का मौका दिया गया.

7. कई वर्षों तक मामले सुप्त पड़े रहे. 25.08.1998 को तीन जजों की बेंच ने निर्देश दिया कि इन मामलों को संविधान पीठ के समक्ष रखा जाए।

8. इस तरह ये मामले संविधान पीठ के सामने विचार के लिए आये हैं। हमने विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री मोहन परासरन और प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अशोक एच.देसाई को सुना है।

9. यह तुरंत देखा जा सकता है कि विद्धान सॉलिसिटर जनरल और प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील बहस के दौरान इस बात पर सहमत हुए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत अवमानना के लिए स्वत: संज्ञान की शक्ति का प्रयोग करने के लिए, 1971 अधिनियम की धारा 20 में प्रदान की गई सीमा लागू नहीं होती है। कानूनी स्थिति के बारे में हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है कि भारत के

सर्वोच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों पर कोई निहित या व्यक्त सीमाएँ नहीं हैं और इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 129 में कोई सीमाएँ नहीं पढ़ी जा सकती हैं।

10. दो प्रमुख प्रश्न जो विचार के लिए उठते हैं और जिनका हमें उत्तर चाहिए, वे इस प्रकार हैं:

(i) जब सर्वोच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश को 1952 अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो क्या उसके पास सर्वोच्च न्यायालय की सभी शक्तियां और अधिकार क्षेत्र होते हैं? दूसरे शब्दों में, क्या एक आयुक्त के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा निभाए गए कार्य पूरी तरह से वैधानिक कार्य हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में निहित क्षेत्राधिकार से स्वतंत्र हैं?

(ii) क्या अवमानना कार्यवाही में सत्य को बचाव के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है?

11. हम पहले दूसरा प्रश्न लेंगे। कुछ सामान्य कानून वाले देश यह प्रावधान करते हैं कि यदि टिप्पणी सार्वजनिक लाभ के लिए भी हो तो सच्चाई बचाव हो सकती है। बहुत पहले अंबार्ड में प्रिवी काउंसिल ने माना था कि न्यायाधीशों या अदालतों की तर्कसंगत या वैध आलोचना अदालत की अवमानना नहीं है। प्रिवी काउंसिल ने अभिनिर्धारित किया:

> "आलोचना का मार्ग एक सार्वजनिक मार्ग है; गलत रास्ते पर चलने वालों को इसमें गलती करने की अनुमति है: बशर्ते कि जनता के सदस्य न्याय प्रशासन में भाग लेने वाले लोगों पर अनुचित उद्देश्यों का आरोप लगाने से बचें, और वास्तव में आलोचना के अधिकार का प्रयोग कर रहे हों, और द्धेषपूर्ण कार्य नहीं करने या न्याय प्रशासन को ख़राब करने का प्रयास नहीं करने पर, वे प्रतिरक्षित हैं। न्याय एक

बंधा हुआ गुण नहीं है: उसे सामान्य पुरुषों की जांच और सम्मानजनक, भले ही मुखर हो, टिप्पणियों का सामना करने की अनुमति दी जानी चाहिए।"

12. विल्स में ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय ने सुझाव दिया कि यदि टिप्पणी सार्वजनिक लाभ के लिए भी हो तो सच्चाई बचाव हो सकती है। इसमें कहा गया, "...सच्चाई का रहस्योद्घाटन - सभी घटनाओं पर जब इसका रहस्योद्घाटन सार्वजनिक लाभ के लिए होता है - और सच्चाई सामने आने के बावजूद तथ्य के आधार पर निष्पक्ष आलोचना करना अदालत की अवमानना नहीं है या की गई आलोचना अदालत या न्यायाधीश को जनता के विश्वास से वंचित करने जैसी है..."।

13. अवमानना कार्यवाही में बचाव के रूप में सत्य के संबंध में कानूनी स्थिति अब 1971 अधिनियम की धारा 13 (2006 के अधिनियम 6 द्वारा प्रतिस्थापित) द्वारा वैधानिक रूप से तय की गई है। 2006 के अधिनियम 6 द्वारा धारा 13 में संशोधन के उद्देश्यों और कारणों का विवरण इस प्रकार है:

"न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 के मौजूदा प्रावधानों की विभिन्न न्यायिक निर्णयों में इस आशय से व्याख्या की गई है कि अदालत की अवमानना के आरोप में सच्चाई को बचाव के रूप में पेश नहीं किया जा सकता है।

2. संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीआरडब्ल्यूसी) ने भी अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की है कि अवमानना के मामलों में, सत्य द्वारा औचित्य की रक्षा की अनुमति देने के लिए न्यायालय खुला होगा।

3. सरकार को सलाह दी गई है कि उपरोक्त प्रावधान प्रदान करने के लिए न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 में संशोधन प्रक्रिया में निष्पक्षता लाएगा और संविधान के अनुच्छेद 21 की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

4. न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 13 कुछ ऐसी परिस्थितियाँ प्रदान करती है जिनके तहत अवमानना दंडनीय नहीं है। इसलिए, उक्त धारा को एक संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है।

5. न्यायालय की अवमानना (संशोधन) विधेयक, 2003 8 मई, 2003 को लोकसभा में पेश किया गया था और इसे जांच के लिए गृह मामलों की विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया था। माननीय समिति ने 2 सितंबर, 2003 को आयोजित अपनी बैठक में उक्त विधेयक पर विचार किया। हालाँकि, 13 वीं लोकसभा के विघटन के साथ, न्यायालय की अवमानना (संशोधन) विधेयक, 2003 समाप्त हो गया। उक्त विधेयक को मसौदा प्रकृति के संशोधनों के साथ फिर से पेश करने का प्रस्ताव है।"

14. खंड 13(बी), अब स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि अवमानना कार्यवाही में सत्य वैध बचाव हो सकता है। धारा 13, जिसमें दो खंड (ए) और (बी) हैं, अब इस प्रकार है:

"13. कुछ मामलों में अवमानना दंडनीय नहीं है- तत्समय लागू किसी भी कानून में किसी बात के होते हुए भी,-

(ए) कोई भी अदालत अदालत की अवमानना के लिए इस अधिनियम के तहत सजा नहीं देगी जब तक कि वह संतुष्ट न हो कि अवमानना ऐसी प्रकृति की है कि यह न्याय के उचित पाठ्यक्रम में काफी हद तक हस्तक्षेप करती है, या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखती है;

(बी) अदालत, अदालत की अवमानना के लिए किसी भी कार्यवाही में, एक वैध बचाव के रूप में सत्य द्वारा औचित्य की अनुमति दे सकती है यदि वह संतुष्ट है कि यह सार्वजनिक हित में है और उक्त बचाव को लागू करने का अनुरोध प्रामाणिक है।"

15. न्यायालय अब सत्य को बचाव के रूप में अनुमति दे सकता है यदि दो चीजें संतुष्ट हैं, अर्थात, (i) यह सार्वजनिक हित में है और (ii) उक्त बचाव को लागू करने का अनुरोध प्रामाणिक है।

16. इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ आर.के. जैन के पास 2006 के अधिनियम 6 द्वारा प्रतिस्थापित 1971 अधिनियम की धारा 13 पर विचार करने का अवसर था। पैरा 39 (रिपोर्ट का पृष्ठ 311) में, न्यायालय ने कहा:

...प्रतिस्थापित धारा 13 हमारी मूल्य प्रणाली के मूल सिद्धांतों में से एक यानी सत्य की एक महत्वपूर्ण विधायी मान्यता का प्रतिनिधित्व करती है। संशोधित धारा अदालत को किसी भी अवमानना कार्यवाही में वैध बचाव के रूप में सत्य द्वारा औचित्य की अनुमति देने में सक्षम बनाती है यदि वह संतुष्ट है कि ऐसा बचाव सार्वजनिक हित में है और बचाव को लागू करने का अनुरोध प्रामाणिक है। हमारे विचार में, यदि किसी भाषण या लेख, संपादकीय आदि में कुछ ऐसा शामिल है जो अवमाननापूर्ण प्रतीत होता है और इस न्यायालय या उच्च न्यायालय को अधिनियम और संविधान के अनुच्छेद 129 और 215 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए कहा जाता है, तो सच्चाई आमतौर पर होनी चाहिए बचाव के रूप में अनुमति दी जानी चाहिए जब तक कि अदालत यह न समझ ले कि यह अदालत को बदनाम करने के जानबूझकर या दुर्भावनापूर्ण प्रयास के परिणामों से बचने के लिए केवल एक छलावा है या न्याय का प्रशासन मे हस्तक्षेप है। चूंकि, याचिकाकर्ता ने यह सुझाव भी नहीं दिया है कि संपादकीय में जो उल्लेख किया गया है वह गलत है या प्रतिवादी ने तथ्यों का

विकृत संस्करण प्रस्तुत किया है, इसलिए प्रतिवादी के इस दावे को खारिज करने का कोई औचित्य नहीं है कि उसने जो कुछ भी लिखा है वह सच्चे तथ्यों पर आधारित है। और संपादकीय लिखने का एकमात्र उद्देश्य संबंधित अधिकारियों को सुधारात्मक/उपचारात्मक उपाय करने में सक्षम बनाना था।"

इस प्रकार, दो न्यायाधीशों की पीठ ने माना है कि संशोधित धारा अदालत को किसी भी अवमानना कार्यवाही में वैध बचाव के रूप में सत्य द्वारा औचित्य की अनुमति देने में सक्षम बनाती है यदि वह संतुष्ट है कि ऐसा बचाव सार्वजनिक हित में है और बचाव को लागू करने का अनुरोध प्रामाणिक है। हम आर.के. जैन मामले में दो न्यायाधीशों की पीठ के विचार को स्वीकार करते हैं। दूसरे प्रश्न के संबंध में और कुछ भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि अवमानना कानून में संशोधन ने इस प्रश्न को प्रभावी रूप से निरर्थक बना दिया है।

17. अब पहले प्रश्न पर विचार करना उचित है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय का एक मौजूदा न्यायाधीश, जिसे 1952 के अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, उसके पास सुप्रीम कोर्ट की सभी शक्तियां और अधिकार क्षेत्र हैं। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, दो अधिनियमों, अर्थात् 1971 अधिनियम और 1952 अधिनियम, के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख करना उचित है। अदालतों की अवमाननाओं को दंडित करने में कुछ अदालतों की शक्तियों को परिभाषित करने और सीमित करने और उनके संबंध में उनकी प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए संसद द्वारा 1971 अधिनियम अधिनियमित किया गया है। धारा 2(ए) "अदालत की अवमानना" को 'सिविल अवमानना' या 'आपराधिक अवमानना' के रूप में परिभाषित करती है। सिविल अवमानना को धारा 2(बी) में परिभाषित किया गया है जबकि धारा 2(सी) में आपराधिक अवमानना को परिभाषित किया गया है। नागरिक अवमानना की

परिभाषा को छोड़कर, हम 1971 के अधिनियम में आपराधिक अवमानना की परिभाषा को पुन: पेश कर सकते हैं, जिसमें लिखा है:

"2(सी) "आपराधिक अवमानना" का अर्थ है किसी भी मामले का प्रकाशन (चाहे शब्दों द्वारा, बोले गए या लिखित, या संकेतों द्वारा, या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा, या अन्यथा) या कोई अन्य कार्य करना जो भी हो-

(i) किसी भी न्यायालय को लांछित करता है या लांछित करने की प्रवृत्ति रखता है, या उसके अधिकार को कम करता है या कम करने की प्रवृत्ति रखता है; या

(ii) किसी भी न्यायिक कार्यवाही के उचित पाठ्यक्रम में पूर्वाग्रह, या हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता है; या

(iii) किसी अन्य तरीके से न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता है, या बाधा डालता है या बाधा डालने की प्रवृत्ति रखता है।"

18. पहले प्रश्न का उत्तर देने के लिए तीन अभिव्यक्तियाँ, खंड (i) में "न्यायालय", खंड (ii) में "न्यायिक कार्यवाही" और धारा 2(सी) के खंड (iii) में "न्याय प्रशासन" वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। अधिनियम 1971 की धारा 12 और 15 अन्य दो धाराएं हैं जिनका कुछ प्रभाव है। धारा 12 न्यायालय की अवमानना के लिए सजा का प्रावधान करती है। धारा 15 सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या महाधिवक्ता द्वारा दिये गये प्रस्ताव पर या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा महाधिवक्ता की लिखित सहमति से दिए गए प्रस्ताव पर आपराधिक अवमानना के संज्ञान से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट के संबंध में धारा 15(1) के खंड (ए) और (बी) में "एडवोकेट जनरल" अभिव्यक्ति का अर्थ अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल है।

19. 1952 का अधिनियम जांच आयोगों की नियुक्ति और ऐसे आयोगों को कुछ शक्तियां प्रदान करने का प्रावधान करता है। धारा 2(ए)(i) "उचित सरकार" को

परिभाषित करती है जिसका अर्थ है केंद्र सरकार, सूची I या सूची II या सूची III में सूचीबद्ध किसी भी प्रविष्टि से संबंधित किसी भी मामले की जांच करने के लिए उसके द्वारा नियुक्त आयोग के संबंध में। संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची II या सूची III में सूचीबद्ध किसी भी प्रविष्टि से संबंधित किसी भी मामले की जांच करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोग के संबंध में। जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में एक अलग प्रावधान है। धारा 4 और 5 आयोग की शक्तियों और अतिरिक्त शक्तियों से संबंधित हैं। धारा 4 के तहत, आयोग के पास मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत मुकदमे की सुनवाई करते समय एक सिविल अदालत की शक्तियां हैं, अर्थात् (ए) भारत के किसी भी हिस्से से किसी भी व्यक्ति को बुलाना और उसकी उपस्थिति को लागू करना और शपथ पर उसकी जाँच करना; (बी) किसी दस्तावेज़ की खोज और उत्पादन की आवश्यकता; (सी) शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना; (डी) किसी अदालत या कार्यालय से किसी सार्वजनिक रिकॉर्ड या उसकी प्रति की मांग करना; (ई) गवाहों या दस्तावेजों आदि की जांच के लिए आयोग जारी करना। धारा 5(4) के तहत, आयोग को एक सिविल कोर्ट माना जाता है और जब धारा 175, धारा 178, धारा 179, धारा 180 या में वर्णित कोई अपराध होता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 228 आयोग की उपस्थिति में की जाती है, आयोग अपराध के तथ्यों और दंड प्रक्रिया संहिता में दिए गए अनुसार अभियुक्त के बयान को दर्ज करने के बाद मामले की अन्वीक्षा के लिये अधिकार क्षेत्र प्रापत मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है। धारा 5(5) के तहत, आयोग के समक्ष किसी भी कार्यवाही को भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थ के तहत न्यायिक कार्यवाही माना जाता है।

20. धारा 5ए आयोग को पूछताछ से संबंधित जांच करने के लिए कुछ अधिकारियों और जांच एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग करने का अधिकार देती है। धारा 10 आयोग के प्रत्येक सदस्य के लिए प्रावधान करती है और अधिनियम के तहत

कार्यों के अभ्यास में आयोग द्वारा नियुक्त या अधिकृत प्रत्येक अधिकारी को आईपीसी की धारा 21 के अर्थ में एक लोक सेवक माना जाता है।

21. धारा 10ए आयोग या उसके किसी सदस्य को बदनाम करने वाले कृत्यों के लिए दंड का प्रावधान करती है। यह प्रावधान उच्च न्यायालय को आयोग के किसी सदस्य या आयोग द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा की गई लिखित शिकायत पर उप-धारा (1) में बताए गए अपराध का संज्ञान लेने की शक्ति प्रदान करता है। उप-धारा (5) के तहत, उप-धारा (1) के तहत किसी अपराध का संज्ञान लेने वाले उच्च न्यायालय को एक मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष पुलिस रिपोर्ट के अलावा अन्यथा शुरू किए गए वारंट मामलों की सुनवाई की प्रक्रिया के अनुसार मामले की सुनवाई करने का आदेश दिया गया है। धारा 10ए इस प्रकार है:

"10ए - आयोग या उसके किसी सदस्य को बदनाम करने वाले कृत्यों के लिए दंड- (1) यदि कोई व्यक्ति, बोले गए या पढ़े जाने वाले शब्दों के माध्यम से, कोई बयान देता है या प्रकाशित करता है या कोई अन्य कार्य करता है, जिसके लिए गणना की जाती है आयोग या उसके किसी भी सदस्य को बदनाम करने पर उसे छह महीने तक की साधारण कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, जब उप-धारा (1) के तहत कोई अपराध किया गया हो, तो उच्च न्यायालय ऐसे अपराध का संज्ञान ले सकता है, मामले को सौंपे बिना, आयोग के किसी सदस्य या आयोग द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा की गई लिखित शिकायत पर।

(3) उप-धारा (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक शिकायत उन तथ्यों को सामने रखेगी जो कथित अपराध का गठन करते हैं, ऐसे अपराध की प्रकृति और ऐसे अन्य विवरण जो

कथित अपराध के आरोपी को नोटिस देने के लिए उचित रूप से पर्याप्त हैं। उसके द्वारा प्रतिबद्ध किया गया है.

(4) कोई भी उच्च न्यायालय उप-धारा (1) के तहत किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा जब तक कि शिकायत उस तारीख से छह महीने के भीतर नहीं की जाती जिस दिन अपराध होने का आरोप लगाया गया है।

(5) उप-धारा (1) के तहत किसी अपराध का संज्ञान लेने वाला उच्च न्यायालय मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष पुलिस रिपोर्ट के अलावा अन्यथा शुरू किए गए वारंट मामलों की सुनवाई की प्रक्रिया के अनुसार मामले की सुनवाई करेगा:

बशर्ते कि ऐसे मुकदमे में शिकायतकर्ता के रूप में या अन्यथा आयोग के किसी सदस्य की व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है।

(6) आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973, (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, अपील उच्च न्यायालय के किसी भी निर्णय से लेकर उच्चतम न्यायालय तक, तथ्यों और कानून दोनों के आधार पर, अधिकार के मामले के रूप में की जाएगी।

(7) उप-धारा (6) के तहत सर्वोच्च न्यायालय में प्रत्येक अपील अपील किए गए फैसले की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर की जाएगी:

बशर्ते कि, उच्चतम न्यायालय तीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद अपील पर विचार कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि अपीलकर्ता के पास 30 दिन के भीतर अपील दायर नहीं करने का पर्याप्त कारण है।

22. जैसा कि ऊपर से देखा गया है, आयोग के पास उस धारा में निर्धारित सीमित उद्देश्य के लिए सिविल न्यायालय की शक्तियाँ हैं। धारा 5(4) के प्रयोजनों के लिए इसे सिविल न्यायालय के रूप में भी माना जाता है। आयोग के समक्ष की कार्यवाही को भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थ में न्यायिक

कार्यवाही माना जाता है। लेकिन वास्तविक मुद्दे यह हैं: क्या उपरोक्त प्रावधान विशेष रूप से और 1952 का अधिनियम आम तौर पर धारा 2(सी)(आई) के तहत "न्यायालय" के अर्थ के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश वाले आयोग को लाएगा? क्या आयोग के समक्ष कार्यवाही धारा 2(सी)(ii) के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही है? क्या ऐसे आयोग की कार्यप्रणाली धारा 2(सी)(iii) के अर्थ के अंतर्गत न्याय प्रशासन का हिस्सा है?

23. हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि 1952 अधिनियम के तहत नियुक्त आयोग के कार्य न्यायिक कार्यों या न्यायिक शक्ति का निर्वहन करने वाली संस्था की तरह नहीं हैं। हमारे विचार में 1952 अधिनियम के तहत नियुक्त आयोग एक न्यायालय नहीं है और आयोग द्वारा तथ्यों की जांच या निर्धारण करना न्यायिक चरित्र का नहीं है।

24. भारतीय दंड संहिता की धारा 19 और 20 "न्यायालय" और "न्यायालय" शब्दों को इस प्रकार परिभाषित करती है:

"19. "न्यायाधीश" शब्द न केवल हर उस व्यक्ति को दर्शाता है जिसे आधिकारिक तौर पर न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है, बल्कि हर उस व्यक्ति को भी दर्शाता है, जिसे किसी भी कानूनी कार्यवाही, नागरिक या आपराधिक, में एक निश्चित निर्णय या निर्णय देने के लिए कानून द्वारा सशक्त किया गया है। जिसके विरुद्ध यदि अपील नहीं की गई तो वह अंतिम होगा, या ऐसा निर्णय जिसकी पुष्टि यदि किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा की गई हो तो वह अंतिम होगा, या

व्यक्तियों के समूह में से कौन एक है, व्यक्तियों के किस निकाय को ऐसा निर्णय देने के लिए कानून द्वारा अधिकार प्राप्त है।

20. शब्द "न्यायालय" एक न्यायाधीश को दर्शाता है जो कानून द्वारा अकेले न्यायिक रूप से कार्य करने के लिए सशक्त है, या न्यायाधीशों का एक निकाय जो कानून द्वारा एक निकाय के रूप में न्यायिक रूप से कार्य करने के लिए सशक्त है, जब ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीशों का निकाय न्यायिक रूप से कार्य कर रहा हो,"

25. हालाँकि 1971 का अधिनियम 'न्यायालय' शब्द को परिभाषित नहीं करता है, लेकिन हमारी राय में, उस अधिनियम के तहत 'न्यायालय' का अर्थ वह प्राधिकारी है जिसके पास निर्णय देने की कानूनी शक्ति है, जो कि यदि किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्टि की जाती है, तो वह निश्चित होगा। न्यायालय एक संस्था है जिसके पास निश्चित निर्णय देकर कानूनी अधिकारों को विनियमित करने और कानूनी मंजूरी द्वारा अपने आदेशों को लागू करने की शक्ति है और यदि साक्ष्य लेने और शपथ लेने जैसे मामलों में इसकी प्रक्रिया न्यायिक है, तो यह एक अदालत है1 1952 अधिनियम के तहत गठित आयोग न्यायालय के इन प्रमुख परीक्षणों को पूरा नहीं करता है।

26. स्टीफन (इंग्लैंड के कानूनों पर स्टीफन की टिप्पणियाँ, 6 वां संस्करण, पृष्ठ 383) के अनुसार, प्रत्येक न्यायालय में कम से कम तीन घटक भाग होने चाहिए-'अभिनेता', 'रेउस' और 'ज्यूडेक्स': 'अभिनेता' ', जो चोट लगने की शिकायत करता है; 'रेउस' या प्रतिवादी, जिसे संतुष्टि देने के लिए बुलाया जाता है; और 'ज्यूडेक्स' या न्यायिक शक्ति, जो तथ्य की सच्चाई की जांच करती है और तथ्य पर उत्पन्न होने वाले कानून का निर्धारण करती है और यदि कोई चोट लगती है, तो पता लगाती है, और अपने अधिकारियों द्वारा उपाय लागू करती है।

27. भारत बैंक लिमिटेड मामले में, संविधान पीठ इस सवाल से घिर गई थी कि क्या औद्योगिक न्यायाधिकरण भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अर्थ के

तहत एक अदालत है। मेहर चंद महाजन, न्यायाधिपति (जैसा कि वह तब थे) ने हडार्ट पार्कर एंड कंपनी में ग्रिफ़िथ, मुख्यन्यायाधिपति के बयान का उल्लेख किया और कहा, "यदि कोई निकाय जिसके पास बंधन देने की शक्ति है और आधिकारिक निर्णय कार्रवाई करने में सक्षम होता है ताकि उस निर्णय को लागू किया जा सके, लेकिन केवल तभी, उद्धृत परिभाषा के अनुसार, न्यायिक शक्ति के सभी गुण स्पष्ट रूप से मौजूद होते हैं।" मुखर्जी, न्यायाधिपति। शेल कंपनी के विचार पर, हडार्ट पार्कर एंड कंपनी और रोला कंपनी में कहा गया है, "अन्य मौलिक परीक्षण जो एक न्यायिक को अर्ध-न्यायिक या प्रशासनिक निकाय से अलग करता है, वह यह है कि पहला कानून के अनुसार विवादों का फैसला करता है, जबकि दूसरा अपने फैसले के लिये कानून का सख्ती से पालन करने के लिए बाध्य नहीं है।" पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर तथ्यों की जांच न्यायिक और अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरणों दोनों में एक सामान्य विशेषता हो सकती है, लेकिन दोनों के बीच अंतर इस तथ्य में निहित है कि न्यायिक कार्यवाही में न्यायाधीश को पाए गए तथ्यों पर आवेदन करना होता है, देश का कानून जो निश्चित और एक समान है। दूसरी ओर, अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरण पक्षकारो के बीच मतभेदों पर अपना निर्णय कानून के निश्चित नियमों के अनुसार नहीं, बल्कि प्रशासनिक नीति या सुविधा के सिद्धांतों या किसी विशेष परिस्थितियों में न्यायसंगत और उचित प्रतीत होने वाले प्रकरण पर देता है। दूसरे शब्दों में, प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा अपने निर्णय पर आने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया वह नहीं है जिसे "न्यायिक प्रक्रिया" के रूप में जाना जाता है।

28. ब्रजनंदन सिन्हा के मामले में, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ को इस प्रश्न पर विचार करने का अवसर मिला कि क्या लोक सेवक (पूछताछ) अधिनियम, 1850 (1850 का अधिनियम 37) के तहत नियुक्त आयुक्त एक न्यायालय है। उस मामले में, कोक ऑन लिटलटन और स्ट्राउड को संदर्भित किया गया

था जो कहता है कि "न्यायालय" वह स्थान है जहां न्याय न्यायिक रूप से प्रशासित किया जाता है। न्यायालय ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 और भारतीय दंड संहिता की धारा 19 और 20 पर भी विचार किया और फिर देखा, "एक निश्चित फैसले की घोषणा, इस प्रकार निश्चित निर्णय को न्यायालय के लिए अनिवार्य माना जाता है और जब तक किसी व्यक्ति या व्यक्तियो की निकाय द्वारा कोई बाध्यकारी और आधिकारिक निर्णय नहीं सुनाया जाता है। यह भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि वह या वे एक न्यायालय का गठन करते हैं।" भारत बैंक लिमिटेड में भी मकबूल हुसैन और एस.ए. वेंकटरमन में इस न्यायालय के निर्णयों का भी उल्लेख किया गया था और यह नोट किया गया था कि मकबूल हुसैन के बाद एस.ए. वेंकटरमन[13] में, संविधान पीठ ने निर्धारित किया था कि अंतिमता और आधिकारिकता दोनों न्यायिक घोषणा के आवश्यक परीक्षण थे। न्यायालय ने कहा कि शब्द के सख्त अर्थ में न्यायालय का गठन करने के लिए, एक आवश्यक शर्त यह है कि न्यायालय के पास न्यायिक न्यायाधिकरण के कुछ प्रावधानों के अलावा, एक निर्णय या एक निश्चित निर्णय देने की शक्ति होनी चाहिए जो इसमें अंतिमता और प्राधिकार है जो न्यायिक घोषणा के आवश्यक परीक्षण हैं। लोक सेवक (पूछताछ) अधिनियम के प्रावधानों के साथ-साथ न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के संदर्भ में, तीन न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि लोक सेवक (पूछताछ) अधिनियम के तहत नियुक्त आयुक्त न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1952 के अर्थ में एक न्यायालय नहीं है।

29. हम ब्रजनंदन सिन्हा द्वारा बताई गई कानूनी स्थिति से पूरी तरह सहमत हैं और उसका अनुमोदन करते हैं।

30. मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ का निर्णय: "द मेल" के संपादक श्री हेल्स और अन्य 14 अब विचार करने योग्य हैं। यह एक ऐसा मामला था जहां मद्रास उच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश को औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा

7 के तहत औद्योगिक न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। अवमाननाकर्ताओं पर जिस कथित अवमानना का आरोप लगाया गया था, वह दोनों औद्योगिक न्यायाधिकरण की कार्यवाही के संबंध में थे, हालांकि औद्योगिक न्यायाधिकरण की अध्यक्षता मद्रास उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश ने की थी। समाचार पत्र "द मेल" के स्वामित्व वाली अमलगमेशन लिमिटेड के श्रमिकों और प्रबंधन के बीच विवाद औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष निर्णय के लिए आया। न्यायाधिकरण द्वारा संपादक गोविंद स्वामीनाथन और संपादक हेलेस के वकील को यह बताने के लिए अवमानना नोटिस जारी किया गया था कि न्यायाधिकरण की आलोचना के लिए अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जा सकती है। प्रतिवादी ने कारण बताओ नोटिस को इस आधार पर चुनौती दी कि ट्रिब्यूनल, हालांकि एक मौजूदा न्यायाधीश की अध्यक्षता में है, के पास अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति नहीं है। उपरोक्त चुनौती से निपटने के दौरान, मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने माना कि उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को जब औद्योगिक न्यायाधिकरण के एकमात्र सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था, तो उसके पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत भी न्यायाधिकरण की अवमानना के लिए व्यक्तियों को दंडित करने के लिए उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की शक्तियां नहीं थीं।

31. पी. राजंगम मामले में मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ के पास इस सवाल पर विचार करने का अवसर था कि क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 176 सपठित मद्रास राज्य सरकार के द्वारा जारी पुलिस स्थाई आदेश के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा की गई जांच को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी की जा सकती है। इस प्रश्न से निपटने के दौरान, ऐसी जांच की प्रकृति के संबंध में मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष मुख्य पहलू यह था कि क्या यह न्यायिक या अर्ध न्यायिक या गैर न्यायिक था। खंडपीठ ने "ब्रजनंदन सिन्हा" मामले में इस न्यायालय के फैसले का

हवाला दिया और अंततः माना कि ऐसी जांच का उद्देश्य उन सामग्रियों को प्रस्तुत करने से ज्यादा कुछ नहीं है जिन पर कार्रवाई की जा सकती है या नहीं और रिपोर्ट अपने आप में पूरी तरह से सिफारिशी होगी न कि एक प्रभावी स्वतंत्र रूप से ।

32. श्री राम कृष्ण डालमिया मामले में, इस न्यायालय ने माना कि 1952 अधिनियम के तहत आयोग द्वारा की गई जांच न तो न्यायिक थी और न ही अर्ध न्यायिक कार्यवाही थी जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उचित रिट के मुद्दे को आकर्षित करती थी।

33. डॉ. बलिराम वामन हिरय मामले में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ इस सवाल से चिंतित थी कि क्या 1952 अधिनियम की धारा 3 के तहत गठित जांच आयोग दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 (1) (बी) के प्रयोजनों के लिए एक न्यायालय है। न्यायालय ने कहा:

> "जांच आयोग उचित रूप से तथाकथित अदालत नहीं है। एक आयोग स्पष्ट रूप से उपयुक्त सरकार द्वारा 'अपने मन की जानकारी के लिए' नियुक्त किया जाता है ताकि वह यह निर्णय ले सके कि क्या कार्रवाई की जानी है। इसलिए यह एक आयोग है, तथ्य-खोज निकाय को पक्षकारो के अधिकारों पर निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है और इसका कोई न्यायिक कार्य नहीं है। सरकार इसकी सिफारिशों को स्वीकार करने या इसके निष्कर्षों पर कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है। केवल तथ्य यह है कि इसके द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया कानूनी है चरित्र और इसमें शपथ दिलाने की शक्ति होने से इसे अदालत का दर्जा नहीं मिलेगा।"

न्यायालय ने आगे कहा:

"एक अदालत के लिए कम से कम जो आवश्यक है वह है 'निश्चित निर्णय' देने की क्षमता, और केवल इसलिए कि उसके द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया कानूनी चरित्र की है और उसके पास शपथ दिलाने की शक्ति है, उसे अदालत का दर्जा नहीं मिल जाएगा अदालत। ऐसा होने पर, यह माना जाना चाहिए कि जांच आयोग अधिनियम की धारा 3(1) के तहत उपयुक्त सरकार द्वारा नियुक्त जांच आयोग संहिता की धारा 195 के प्रयोजनों के लिए एक अदालत नहीं है।"

33.1. न्यायालय एम. वी. राजवाड़े मामले में नागपुर उच्च न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों से सहमत हुआ:

"संबंधित आयोग स्पष्ट रूप से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था" अपने मन की जानकारी के लिए, ताकि वह अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए, अपने अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच का आदेश देने में "न्याय और समानता के आदेशों के अलावा" कार्य न करे। इसलिए, यह एक तथ्य-खोज निकाय था, न्यायिक प्रकृति के किसी भी दस्तावेज़ का उत्पादन किए बिना केवल सरकार के दिमाग को निर्देश देना है। दोनों मामले समानांतर हैं, और निर्णय 'इन री महाराजा माधव सिंह (डी) [एलआर (1905) 31 आईए 239] के अनुसार होना चाहिए कि, आयोग कोई अदालत नहीं थी।

"न्यायालय" शब्द को न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1952 में परिभाषित नहीं किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में इसकी परिभाषा संपूर्ण नहीं है और केवल अधिनियम के उद्देश्यों के लिए है। हालाँकि, न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1952 एक "न्यायालय" पर विचार करता है, जैसा कि धारा 20, दंड संहिता, 1860 में परिभाषित किया गया है, "एक न्यायाधीश जो न्यायिक रूप से कार्य

करने के लिए कानून द्वारा सशक्त है" को दर्शाता है। धारा 19 में "न्यायाधीश" शब्द को प्रत्येक व्यक्ति को सूचित करने के रूप में परिभाषित किया गया है-

> "किसी भी कानूनी कार्यवाही, नागरिक या आपराधिक, में एक निश्चित निर्णय देने के लिए कानून द्वारा अधिकार प्राप्त है, या एक निर्णय, जिसके खिलाफ अपील नहीं की जाती है, तो वह निश्चित होगा, या एक निर्णय जो, यदि किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्टि की जाती है, तो निश्चित होगा..."

उपरोक्त परिभाषा में, "न्यायालय" का न्यूनतम परीक्षण, इसलिए, निर्णय देने की कानूनी शक्ति है, जो यदि किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्टि की जाती है, तो निश्चित होगी। ऐसा ही मामला लोक सेवक (पूछताछ) अधिनियम, 1850 के तहत नियुक्त आयोग का है, जिसकी सिफारिशें सरकार द्वारा पुष्टि किए जाने पर एक निश्चित निर्णय बनती हैं। हालाँकि, यह जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत नियुक्त आयोग के मामले में नहीं है, जिसके निष्कर्षों को कानून द्वारा किसी भी स्तर पर किसी भी प्राधिकारी द्वारा पुष्टि के लिए उत्तरदायी नहीं माना जाता है ताकि अंतिम निर्णय का चरित्र ग्रहण किया जा सके।

34. हम डॉ. बलिराम वामन हिरय के विचार से सहमत हैं और एम.वी.राजवाड़े के मामले में नागपुर उच्च न्यायालय के निर्णय का अनुमोदन करते हैं। हम सॉलिसिटर जनरल श्री मोहन परासरन की इस दलील से भी सहमत हैं कि 1952 अधिनियम के तहत नियुक्त आयोग एक वैधानिक आयोग की प्रकृति का है और केवल इसलिए कि जांच आयोग का नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। यह इस न्यायालय की विस्तारित शाखा नहीं बनता है। 1952 अधिनियम के तहत गठित आयोग एक तथ्यान्वेषी निकाय है जो उपयुक्त सरकार को यह निर्णय लेने में

सक्षम बनाता है कि क्या कार्रवाई की जानी है। ऐसे आयोग को पक्षकारो के अधिकारों पर निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है और इसका कोई न्यायिक कार्य नहीं है। सरकार इसकी सिफ़ारिशों को स्वीकार करने या इसके निष्कर्षों पर कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है। केवल यह तथ्य कि आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया कानूनी चरित्र की है और उसे शपथ दिलाने की शक्ति है, उसे न्यायालय का दर्जा नहीं मिल जाएगा। ऐसा होने पर, हमारे विचार में, 1952 अधिनियम के तहत नियुक्त आयोग न्यायालय की अवमानना अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक न्यायालय नहीं है, भले ही इसका नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, 1952 अधिनियम की धारा 10-ए में कोई संदेह नहीं है कि उच्च न्यायालय को आयोग या उसके किसी सदस्य को बदनाम करने वाले कृत्यों के संबंध में शिकायत का संज्ञान लेने की शक्ति प्रदान की गई है। धारा 10-ए इस न्यायालय में अपील के अधिकार के साथ उच्च न्यायालय का संदर्भ देकर आयोग को रचनात्मक अवमानना की शक्ति प्रदान करती है। इसलिए, पहले प्रश्न का हमारा उत्तर नकारात्मक है।

35. उपरोक्त कारणों को देखते हुए अवमानना याचिकाएं खारिज की जाती हैं और अवमानना नोटिस खारिज किए जाते हैं।

कल्पना के.त्रिपाठी

अवमानना याचिकाएं खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उददेश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उददेश्यो के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।